their relocation would be based on a case by case examination of the objections filed by each unit.

मध्यप्रदेश में वन भूमि का बन्दोबस्त

7090. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में वन-भूमि का बन्दोबस्त किन-किन वर्षों में किया गया;

(ख) क्या राज्य के प्रत्येक जिले में वन-विहीन बंजर भूमि को आवश्यकतानुसार राजस्व भूमि में हस्तांतरित करने हेतू तथा उस वन भूमि, जिसपर वहां के निवासियों द्वारा कब्जा करके कई वर्षों से खेती के उपयोग में लाया जा रहा है, के बन्दोबस्त हेतु कोई कार्यवाही की जाएगी; और

(ग) वनों के बीच स्थित "वन ग्रामों" जो गुलामी व शोषण के प्रतीक हैं, में बसे आदिवासियों को भूमि का पट्टा देकर इन वन-ग्रामों को राजस्व विभाग को सौंपने के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के बारे में मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, वन भूमि पर 25-10-1980 से पूर्व के अवैध कब्जों को कतिपय मानदण्डों के पूरा करने की शर्त पर नियमित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

(ग) मंत्रालय के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित वन भूमि को डिनोटिफाई करने के बाद वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा सकता है जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत औपचारिक प्रस्ताव भेजना होता है।

आधिकारिक विकास सहायता और राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के अन्तर्गत जिलों का चयन

7091. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आधिकारिक विकास सहायता और राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के अन्तर्गत राज्य-वार किन-किन जिलों का चयन किया गया है तथा राज्यवार किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी अवधि में कितनी-कितनी धनराशि खर्च किए जाने की योजना है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों की सिफारिशों पर गत तीन वर्षों में किन-किन अधिकारियों को विदेश भेजा गया और उन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) विदेश से लौटने के बाद कितने अधिकारियों को राज्य सरकारों द्वारा परियोजना-क्षेत्रों में ही नियुक्त किया गया है तथा किन-किन एवं कितने-कितने प्राधिकारियों को परियोजना क्षेत्रों से बाहर अन्यत्र नियुक्त किया गया है और उन्हें ऐसे स्थानों पर नियुक्त किए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Yamuna Action Plan

7092. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of ENVIRONMENT & FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Yamuna Action Plan, on the lines of the Ganga Action Plan has since been finalised for cleansing Yamuna;

(b) if so, what are the details of the plan including its cost; and

(c) the steps taken to implement the Yamuna Action Plan so far, indicating the phase-wise targets set under the plan, year-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Yes, Sir. Under the Yamuna Action Plan, pollution abatement works will be taken up in six towns of Haryana and eight towns of U.P. besides Delhi. The list of these towns is given in statement I. (*see* below). The pollution abatement works include interception and diversion of municipal waste water from these towns, setting up of sewage treatment plants to treat the intercepted municipal waste water, construction of low cost toilets and improved crematoria, development of bathing ghats and plantations along the river. The sanctioned cost of these work under the Yamuna Action Plan is Rs. 343.78 crore. This cost would be shared equally between the Central and the concerned State Governments. A loan of Yen 17.77 billion